नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (नासवी)

फुटपाथ की आवाज

राष्ट्रीय समन्यवयक के टेबल से

प्रिय,

स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, 2014 के कार्यान्वयन पर हमारा प्रयास उसी संकल्प के साथ जारी है | हमारे कई सदस्य हमारे आंदोलन के महत्व के सराहना करने में विफल है | वे लगता है कि यह सिर्फ बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का एक कदम है | वे यह नहीं समझते कि जिस शहर को हम पुनः प्राप्त करना चाहते है और जिस जमीन पर हम अपना माल बेचना चाहते हैं वह संपन्न और प्रभावशाली है. इन परिस्थितियों में स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम लागू करना आसान नहीं है | नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि टाउन वेंडिंग कमिटी में स्ट्रीट वेंडर्स के निर्वाचित प्रतिनिधियों को लुभाने में असमर्थ हैं | भारत संभवतः इस ग्लोब पर पहला देश है, जिसने कानून द्वारा नागतिक (स्ट्रीट वेंडर) कि भागीदारी को निर्धारित किया है |

पटना में सड़क विक्रेताओं और स्थानीय वार्ड पार्षदों के बीच हाल में झड़प हुई थी. वेंडर्स वार्ड पार्षद द्वारा सर्वेक्षण में तथा वेंडरों को पहचान पात्र वितरण में हस्तक्षेप आदि का विरोध कर रहें थे | वेंडर ने वार्ड पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कि असंवेदनशील नगर निकायों के कारन इस तरह कि झड़पें होना कर बढ़ाना भी तय है | उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है की स्ट्रीट वेंडर स्थानीय अर्थव्यवस्था और शहरी वितरण प्रणाली में योगदान है | इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने शिकायत निवारण समिति का गठन शुरू कर दिया है | हम इस कदम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं की शेष भारत जल्द ही इसका अनुशरण करेगा |

जय हिन्द,

अरबिंद सिंह

श्रंद्धांजलि

पश्चिम बंगाल में नासवी के प्रमुख सदस्य संगठन एवं राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस(इंटक) के सचिव एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (पश्चिम बंगाल राज्य) रमेंन पांडेय हमारे बीच नहीं रहे| पिछले कुछ माह से उनका इलाज चल रहा था। यदपि उन्होने नासवी के लिए एक मजबूत नेतृत्व का सृजन किया लेकिन नासवी परिवार इस दुखद घड़ी में चंद्रलेखा जी सहित सम्पूर्ण परिवार के साथ है एवं ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रमेंन पांडेय की कमी हमेंशा महसूस करेंगी|

सेल्फ वर्कर्स ग्लोबल का गठन (SWG):

18 जून 2019 को जेनेवा में सेल्फ वर्कर्स ग्लोबल यूनियन की शुरुआत हुई| नासवी (भारत) यू पी टी ए (स्पेन) और एसआईवीएआरए (अर्जेंटीना) ने सेल्फ वर्कर्स ग्लोबल यूनियन को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रचा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे ||| ऐसे समय में जब स्वयं कार्यकर्ता और अनौपचारिक कार्यकर्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं और वैश्विक स्वयं श्रमिकों और अनौपचारिक श्रमिकों का संघर्ष दुनिया भर में हो रहा है, स्व श्रमिकों और अनौपचारिक श्रमिकों को मजबूत, गतिशील, जन आधारित ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियनों के साथ गहरे और अनौपचारिक श्रमिकों को सभी क्षेत्रों में मजबूत जकड बनाने की जरुरत है। सेल्फ वर्कर्स ग्लोबल (एसडब्ल्यूजी इस्फोर्थ) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो वैश्विक व्यापार अर्थव्यवस्था में स्व-नियोजित श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। एसडब्ल्यूजी अपने सभी पहलुओं में स्व-रोजगार की गरिमा की रक्षा करना चाहता है और इसके लिए एसडब्ल्यूजी दुनिया भर में संघों और सहयोगियों के निर्माण प्रक्रिया में है। एसडब्ल्यूजी अपनी तरह का पहला दुनिया भर में स्वरोजगार के जटिल सवाल से जुड़े संगठन का वैश्विक महासंघ है। एसडब्ल्यूजी का इरादा औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंदर और बाहर लाखों स्वरोजगारियों को आवाज देने का है, उनका प्रतिनिधित्व करने का हैं और उनकी जरूरतों के दावों को पूरा करने का है, ताकि स्व-रोजगार के काम की गरिमा हो और अर्थव्यवस्था में इनका योगदान देने लायक हैं।

"हम संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीयता और एकता के साथ" आगे बढ़ते हैं।

नासवी कार्य कारिणी समिति ने बनाई भविष्य योजना

नास - सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर चर्चा

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु कार्यरत है | इस गठजोड़ की मुख्य मांग है कि :

1. **हमें क्षर्मिक के रूप में पहचान व पंजीकरण किया जाय |**
2. **हमें मातृत्व लाभ रु 60,000 दिए जय (5 महीने न्यूनतम वेतन) |**
3. **हमें प्रति माह 5000 रुपये पेंशन (न्यूनतम वेतन का 50%) का भुगतान करें |**
4. **सभी लाभों के साथ हमें इसआई योजना से जोड़े |**
5. **विकृति और मित्र्यु के स्थिति में हमें 5,00,000 रुपये के न्यूनतम क्षतिपूर्ति का भुगतान करें |**

दिनांक 24 जून 2019 को नासवी के कार्यकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह के अध्यक्षता में राजीव नगर पटना में आयोजित की गई| पटना, भागलपुर, जमशेदपुर एवं बनारस में चल रहे परियोजना को कार्यकारणी समिति के समक्ष कार्य करने के तरीके एवं सरकारो के साथ ताल मेंल बिठाने के तौर पर प्रस्तुत किया गया| सभी सदस्यों को अच्छे उदाहरण एवं अभ्यास को विभिन्न नगर निकायो में भी अमल में लाने हेतु सॉफ्ट कॉपी वितरित किए गये |

बैठक में वर्तमान समस्यायों एवं चुनौतियों पर विषय गत परिचर्चा उपरांत एक विस्तृत कार्य योजना बनी |

- वेंडर्स को मजबूत करने हेतु मार्केट कमेंटी का गठन करना, शहर एवं स्टेट लेवेल कमेंटी के क्षमतावर्धन पर जोर देना होगा|
- कार्यकरणी समिति को भी सोशल मीडिया हंडेलिंग हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा, एवं कार्यकरणी समिति में से ही एक सदस्य को दूसरे राज्य का प्रभारी बनाया जाय|
- नए मेंम्बर को नासवी के तरफ से सदस्यता अनुमोदन के बाद सदस्यता किट भेजी जाय|
- टीवीसी में वेंडर्स सदस्यों को बैठक में खुलकर बात करने लगातार प्रशिक्षण करवाने की जरूरत है| टीवीसी की बैठक में वेंडर्स से संबन्धित विभिन्न मुद्दो पर छोटी-छोटी फिल्म की क्लिप बनाई जाएगी| लीडरशिप विकास के लिए फोन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम पर विचार किया जाय |
- ग्रीवान्स रेड्रे सेल कमेंटी बनाने हेतु राज्य अध्यक्ष को पहल करना होगा एवं नासवी मुख्यालय भी सभी राज्यो को पत्र लिखेगा|
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं स्मार्ट सिटी एजेंसी के सतह मिलकर कार्य किया जाएगा एवं उनके फंड का सही सदुपयोग हो यह सुनिश्चित किया जाएगा| वेंडिंग शुल्क निर्धारण हेतु केंद्र से एक दिशा निर्देश निकलवाने हेतु पहल किया जाएगा|
- सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सहकारी समिति को बढ़ाने एवं बनने की जरूरत पर बल दिया जाएगा| वित्तीय सुविधा या मुद्रा लोन की प्रक्रिया से सभी सदस्यों को अवगत करवाया जायेगा|
- नासवी का ई न्यूज़ लेटर सभी तक उपलव्ध हो इस पर सघन रूप से ध्यान दिया जाएगा|
- स्ट्रीट फूड फेस्टिवल से स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए नए रास्ते खुले है एवं अब सरकार उन्हे प्रशिक्षण भी शुरू कर चुकी है अतःयह पूर्व की तरह आयोजित किए जाएगे एवं नई संभावनाओ को भी देखा जाएगा |

वार्षिक आम सभा

वार्षिक आम सभा बंगलोर में अगस्त या सितम्बर निर्धारित

सभी सदस्य वार्षिक आम सभा से पूर्व सदस्यता शुल्क जमा करवाए

सदस्यता शुल्क की राशि 50 पैसे प्रति सदस्य से बढ़ाकर 1 रुप्रति सदस्य

गैर सरकारी संगठन वव्यक्तिगत सदस्यता पूर्व की भाति

फुटपाथी दुकानदार समझें जिम्मेवारी

स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम व स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट वेंडरो के समावेश हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला

नासवी के द्वारा दिनांक 25 जून 2019 को **बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन,पटना** में बिहार के नगरीय निकायों में स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम व स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट वेंडरो के समावेश हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया| कार्यशाला में नासवी कार्यकारणी समिति के सदस्य भी उपस्थित हुए |

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 5% की धन राशि स्ट्रीट वेंडर्स के उत्थान जैसे कार्यक्रम पर खर्च करने का प्रावधान है| इनके रोजगार का संरक्षण करना हमारी भी प्राथमिकता है| कई शहरों में वेंडिंग ज़ोन बनाने की प्रक्रिया चल रही है| वेंडर्स को भी चाहिए की जहां पर उनके लिए व्यवस्था की जा रही है वही से वो अपना व्यवसाय करे |
संजीवपांडे,
टीम लीडर (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)

कार्यशाला में यह बात उभर कर सामने आई कि फूटपाथी दुकानदारों को नियम न करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय कानून के आलोक में बिहार राज्य फूटपाथ दुकानदार (रोजगार की सुरक्षा एवं स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) नियमावली 2017 को पारित किए एवं कई नगर निकायो में स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान हेतु सर्वे भी करवाया गया | वेंडर्स को पहचान पत्र भी दिये जा रहे है एवं वेंडिंग ज़ोन का भी निर्माण किया जा रहा है| कानून के अंतर्गत ग्रीभांस रिड्रेसाल समिति का भी गठन करने की प्रक्रिया चल रही है | लेकिन यह महज़ एक कागजी कार्यवाही ही लगती है, वेंडर्स को इस का प्रत्यक्ष लाभ कहीं भी नहीं मिल रहा है| हर जगह वेंडर्स को हटाया जा रहा है| स्मार्ट सिटी में तो वेंडर्स की स्थिति और भी दयनीय है| नगर निकाय एवं जिला प्रशासन के बीच कोई समन्वय नहीं है| टीवीसी की बैठक मात्र खाना पूर्ति ही साबित होती है, वेंडर्स की बात को अनसुनी कर अधिकारियों द्वारा नो वेंडिंग ज़ोन के बारे में बता दिया जाता है जबकि चिन्हित वेंडिंग ज़ोन में पुनर्वास हेतु कोई योजना भी नहीं बनी| सर्वेक्षण हुए 3 से 4 साल हो गए लेकिन अभी तक जीतने आधार से सत्यापित विक्रेता है उनको भी कार्ड नहीं दिया गया| वही कुछ वेंडर्स प्रतिनिधियों ने बताया कार्ड का कोई मूल्य नहीं है, कोई भी अधिकारी इसे नहीं मानते |

यदपि बिहार सरकार ने कई सार्थक प्रयास किया है पर नगर निकायों ने कैसे प्रतिक्रिया दी है? क्या न्यायिक हस्तक्षेप हैं? राजधानी पटना में ही हमने देखा है कानून को लागु करवाने हेतु कैसे "बाधादौड़" को पार किया । राज्य के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है? क्या यह शहरी आजीविका मिशन व स्मार्ट सिटी अवधारणा के साथ एकीकृत किया गया है?
अरबिन्द सिंह
राष्ट्रीयसमन्वयक,नासवी

आम सहमति है की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं स्मार्ट सिटी केंद्र प्रायोजित योजना है| राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के पुनार्वाशन हेतु केंद्र से फण्ड भी उपलव्ध है| इसीलिए नासवी के राज्य कार्यशाला यह निर्णय लिया गया कि प्रधान मंत्री व मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण करने हेतु सघन अभियान चलाया जाय| आगामी 2 अक्टूबर को राज्यव्यापी फूटपाथ दूकानदारी बंद रखने का आवाहन किया है|
चंद्रप्रकाश सिंह
अध्यक्ष नासवी

राजगीर में वेंडर्स को आईडी कार्ड वितरण : 8 वर्षो के निरंतर संघर्ष के बाद अन्तराष्ट्रिय पर्यटन स्थल राजगीर में फूटपाथ दुकानदारो को नगर पंचायत द्वारा नियमन हेतु सर्वेक्षण कर 350 फूटपाथ दुकानदारों को पहचान पत्र दिया गया |

झारखण्ड की प्रगति

सभी प्रमुख 44 यूएलबी ने नियमानुसार टीवीसी का गठन किया। हालाँकि, अधिकांश ULB में उचित तरीके से TVC की बैठकें नहीं हो सकीं। स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण पूरे शहर में एक वेब सक्षम सर्वेक्षण एप्लिकेशन ऐप के साथ पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण में शामिल किए गए कुल 37,701 स्ट्रीट वेंडरों में से लगभग 17000 विक्रेताओं को पहचान पत्र मिले। हालांकि, कुछ विक्रेताओं को छोड़ दिया गया है जो एनयूएलएम अधिकारी के अनुसार दूसरे चरण में शामिल होंगे। बाकी आईडी कार्ड वितरण जारी है। वेंडिंग जोन की पहचान की गई है।

रांची में एक वेंडिंग जोन "अटल वेंडिंग जोन" बनाया गया है जहां 427 स्ट्रीट वेंडर्स को शिफ्ट किया गया है। बाकी शहरों में वेंडिंग ज़ोन के निर्माण के लिए भूमि की पहचान की गई है।

जमशेदपुए के टिन प्लैट क्षेत्र में वेंडिंग ज़ोन बन कर तैयार है। जल्द ही वेण्डरो को यहाँ शिफ्त करने कि तैयारी की जा रही है। यहाँ कुल 92 दुकाने बन कर तैयार है, और 50 दुकाने बननी है। जुबली पार्क में वेंडिंग जोन निर्माण हेतु नक्शा बनाया जा रहा है|

दिनांक 16 जून को टाउन वेंडिंग समिति के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया |

विजयनगरम शहर में 160 कार्ड निर्गत किये गए |

मेंपमा में बैठक

जिलाधिकारी कार्यालय, धारना गुंटूर

राष्ट्रीय फुटपाथ अन्डू वंदी पित्तकड़ा संघ ने कोझिकोड मेंडिकल कॉलेज में हड़ताली कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए दैनिक वेतन भोगियों की नियमितता की मांग की।

कर्नाटक बीड़ी बदी व्यपारी संगठन पर्व वाककूट शाखा

बेलगाम: बेलगाम महा नागर पालिका पहचान पत्र जारी करने और वेंडिंग जोन बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन

कनाकपर - रामनगर में वेंडिंग जोन का निर्माण

कर्नाटक सरकार द्वारा 24 Jun 2019 को स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का गठन किया गया और बेंगलुरु-कर्नाटक में सड़क विक्रेताओं द्वारा इस दिवस को मनाया गया।

शाहपुर नगर मार्किट, हैदराबाद टीवीसी चेयरमैन द्वारा ग्रीन वेंडिंग जोन घोषित किया गया |

चेन्नई के प्रसिद्ध सड़क विक्रेताओं के बाजार, एन एस सी बोस रोड (पूक्कादै)) में लगातार छापे पड़ रहे हैं। यह बाजार 50 से अधिक वर्षों से जो एक धरोहर है। लेकिन ट्रैफिक रैमसे नाम के एक शख्स ने स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया कि वे ट्रैफिक जाम का कारण हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले को स्वीकार किया, इस मामले में उन्हें वर्ष 2015 में निर्णय मिला। इस मामले में चेन्नई निगम, चेन्नई उच्च न्यायालय को स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और सर्वोच्च न्यायालय के 9/9/2013 के निर्णय बारे में सूचित करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे स्ट्रीट वेंडर्स को खाली न करें, जो उस दिन यानी 9/9/2013 को स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं। हमने काफी संघर्ष किया आखिरकार उन्होंने 2 साल पहले आईडी कार्ड दिया। लेकिन उन्हें आज तक जगह नहीं दी गई और वेंडिंग जोन भी नहीं बनाया गया है। लेकिन रोज छापेमारी कर रहे हैं और उनकी चीजें और उत्पाद (सब्जियां, फूल, फल) जब्त कर रहें है। वे इन सभी चीजों से राहत चाहते हैं और यह भी उम्मीद करते हैं कि हम उनकी रक्षा करें और जगह के आवंटन के लिए

कुछ करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जिसका हम इस महीने सामना कर रहे हैं।

चेन्नई के कोइम्बेडू में मशहूर स्ट्रीट वेंडर्स मार्केट

वडोदरा

वडोदरा शहर में सर्व सेव फ़ूड प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्ट्रीट फ़ूड वेंडरों को उनके रोजगार को बेहतर करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया| 10 चरणों में 500 वेंडरों को प्रशिक्षित किया गया| प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें एप्रन, कैप और ग्लव्स वितरित किये गए | प्रशिक्षण नगर निगम के अगुआई में सफलता से संपन्न हुआ |

प्रशिक्षण मिशन: वडोदरा नगर निगम के साथ गुजरात अध्यक्ष अरविन्द सिन्धा

मसूरी में नासवी के पहल पर टीवीसी का गठन

मसूरी क्षेत्रानान्तर्गत नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में माल रोड से अतिक्रमण के नाम पर सभी रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को नगर पालिका तथा प्रशासन के द्वारा उनकेविक्रयस्थान से हटा दिया गया| शोशल मीडिया पर वाइरल हुए वीडियो के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ | मसूरी में स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए नासवी ने वस्तु स्थिति का जाएजा लेकर पहल की| वहाँ विभिन्न मार्किट में स्थानीय लीडर्स के साथ जाकर भी मुलाकात की, यहाँ पर मसूरी क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में 13 वार्ड है जिसमें मुख्यतः मालरोड, वार्डनंबर 8 में वेंडर्स की जनसँख्या सबसे अधिक है, तथा यही पर ज्यादा वेंडर्स को परेशान किया जाता है, यहाँ कुल वेंडर्स से संख्या 400 से 500 है|

नासवी द्वारा अधिशासी अधिकारी (EO) नगर पालिका परिषद्, SDM को पत्र लिखा गया एवं व्यक्तिगत रूप से मुलाक़ात कर टीवीसी के गठन एवं स्ट्रीट वेंडिंग कानून 2014 एवं राज्य नियमावली का हवाला दिया गया| यदपि टीवीसी का गठन पूर्व में हुआ था मगर ये सिर्फ कागजी खन पूर्ति थी| अधिशासी अधिकारी (EO) नासवी के दलील मानते हुए TVC का गठन हेत पत्र नियमवाली 2016 के धारा 12 (2) के

अनुसार नासवी सहित सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को भेजा गया एवं दिनांक 17-06-2019 को इस की गठन के बैठक का आयोजन किया गया ।

अधिशासी अधिकारी ने नासवी से आग्रह किया कि नगरपालिका परिषद को TVC के गठन तथा रेहड़ी पटरी व्यवसाइयों की उतराखंड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) नियमवाली 2016 को लागु करने तथा सर्वे करने में मदद करें ।

नासवी द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मसूरी में स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़े मुद्दों तथा नगर पालिका एवं प्रशाशन द्वारा , वेंडर्स कानून 2014 तथा उत्तराखंड वेंडर्स नियमावली 2016 का उल्लंघन करते हुए मसूरी में अम्बेडकर चौक से वसीम जूस कार्नर तथा मयूर होटल के समीप तथा अन्य स्थानों से असंवैधानिक रूप से अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े गए रेड़ी पटरी व्यवसयियो को यथास्थिति अविलम्भ बसाने के संदर्भ में पत्र लिखा , जिसपर अनु सचिव , उत्तराखंड शाशन द्वारा संज्ञान लेते हुए, निदेशक शहरी विकास निदेशालय को कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा

हरिद्वार: स्ट्रीट वेंडर्स सह लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष के अगुआई में चंडी घाट मार्ग स्थित कार्याला में एक बैठक का आयोजन किया गया| यह बैठक राज्य फेरी नीति नियमावली को हरिद्वार में लागू करने के सन्दर्भ में था | नगर निगम प्रशासन द्वारा वेंडर्स का सर्वे में पंजीकरण के आधार पर प्रथम चरण में लाइसेंसे और परिचय पत्र मुहैया करने पर भी चर्चा किया गया|

उत्तराखंड बुलेटिन

राज्य फेरी नीति नियमावली को हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में लागू करने को लेकर हुई बैठक

दिल्ली - टी.वी.सी. का चुनाव:

15-07-2018 को प्रथम टाउन वेंडिंग कमिटी का गठन चुनाव के माध्यम से किया गया | जिसमें पूरी दिल्ली में 27 डाउन टाउन वेंडिंग कमेटियों की गठन की गई | जिसमें से 24 टाउन वेंडिंग कमेटियों में 147 सीटें रिक्त रह गई थी | जिसकी पूर्ति के लिए तीनों नगर निगमों के द्वारा 25-05-19 को सर्कुलर जारी कर चुनाव की तारीख की घोषणा किया गया जिसमें आवेदन की प्रक्रिया 30-05-2019 से 07-06- 2019 तक थी | टीवीसी में रिक्त सीटों की पूर्ति के लिए नासवी सक्रिय भूमिका अपनाते हुए सभी रिक्त सीटों पर नासवी समर्थित उम्मीदवार खड़ा किए गये | 30-06-2019 को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और 01-07-2019 को नवनिर्वाचित उम्मीदवारों का घोषणा नगर निगमो के द्वारा कर दिया गया | जिसमें से 80, प्रतिशत सीटों पर नासवी समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई |

नासवी के द्वारा जागरूकता अभियान:

नासवी के द्वारा सरिता विहार, मोड बंद सब्जी मंडी , पुरानी सीमापुरी और दिलशाद गार्डन में फुटपाथी विक्रेताओं को " पथ विक्रेता कानून जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन अधिनियम 2014 " एवं दिल्ली राज्य फेरी नियमावली और स्कीम एवं संगठन की महत्व के बारे में फुटपार्थी विक्रेताओं को जागरूक करने के साथ-साथ उन को संगठित किया गया जिनका नाम इस प्रकार है 1- रेहड़ी पटरी एकता मंच जनता कॉलोनी सरिता विहार |
2- सब्जी मंडी एसोसिएशन मोड़ बंद बदरपुर बॉर्डर |

नासवी का प्रयास: पुरानी सीमापुरी और दिलशाद गार्डन में पुलिस के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर अवैध रूप से हटाए गये फुटपाथी विक्रेताओं को नासवी के द्वारा एस एच ओ महोदय से मीटिंग कर हटाए गए फुटपाथी विक्रेताओं को दोबारा से रोजगार करने की अनुमति दिलाने के साथ साथ उस मार्केट में दलालों के द्वारा अवैध रूप से फुटपाथी विक्रेताओं से की जा रही वसूली पर रोक लगाने के लिए दलालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराया गया |

लखनऊ में 168 जगह को वेंडिंग ज़ोन के लिए चिन्हित

लखनऊ में वेंडर्स की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहे है| बहुत कुछ माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर निर्भर हो गया है| पूर्व में किए गए सर्वेक्षण को नगर निगम ने मानने से इंकार कर दिया| कोर्ट के पहल पर पुनः सर्वे करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई एवं कुल 8 जोन में दिनांक 10 जून तक वेंडर्स से आवेदन मांगे गए| इस बीच निगम ने कुल 15122 पंजीयन पत्र वितरत किए जिस में कुल 12311 लोगो ने ही आवेदन दिया| अब इसका सत्यापन 168 जगह को वेंडिंग ज़ोन के लिए चिन्हित किया जाएगा| मीडिया के खबरों एवं स्थानीय संगठनो के अनुसार कई बाहरी लोगो ने भी फॉर्म जमा किए है एवं वास्तविक वेंडर्स की संख्या 20 से 25 % ही है| नासवी कार्यकरणी सदस्य श्री गोकुल प्रसाद,पटरी दुकानदार कल्याण समिति एवं टाउन वेंडिंग समिति के सदस्य ने नगर आयुक्त सह अध्यक्ष टाउन वेंडिंग कमेटी एवं जिलाधिकारी को पत्र लिख कर विरोध दर्ज किया है| हालांकि लखनऊ नगर निगम ने अभी तक 200 से अधिक जगहो पर वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया है जिसमें लगभग 20 जगहो पर यातायात विभाग ने आपत्ति दर्ज की है|

पटरी दुकानदारों ने कर

12-6-2019

कहीं वेंडिंग प्रमाण पत्र तो कहीं हालात गंभीर

वाराणसी में ही दिनांक 17 जून 2019 को नगर विकास मंत्री के द्वारा नगर निगम के 5 ज़ोन के एक एक वेंडिंग जोन से कुल 250 पटरी दुकानदारो को वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया| नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वेंडर्स को एक क्रम में रहने, गंदगी नहीं फैलाने व स्वास्थ्य व स्वच्छता पर ध्यान देने की बात कही |

आगरा व गाज़ियाबाद में भी पटरी वालों को वेंडिंग प्रमाण पत्र व पहचान पत्र दिये गए है| वहीं हापुर एवं मेंरठ में हालात चिंताजनक है क्यो वहाँ वेंडर्स को लगातार उजाड़ रहे है|

लखनऊ - 168 वेंडिंग जोन चिन्हित

लाटरी द्वारा तय वेंडिंग जोन में जगह आबंटित होगा | बताते चलें कि लखनऊ शहर में कुल 168 वेंडिंग जोन निर्धारित किये गए हैं जबकि कुल 12328 वेंडरों ने आवेदन किया है जिनमें से सिर्फ 8622 को ही जगह मिल पाएगी| यह जानकारी नगर निगम वेंडिंग कमिटी ने नगर आयुक्त जिलाधिकारी को दी है |

वेंडिंग जोन में सामने आया नगर निगम का नया फर्जीवाड़ा

30 तक लाइसेंस न बनवाया तो ठेला जब्त

लखनऊ। नगर निगम बिना लाइसेंस शहर में आइसक्रीम ट्राली, रिक्शा और ठेला चलाने वालों के खिलाफ एक सप्ताह बाद अभियान चलाने जा रहा है। लाइसेंस न मिलने पर जुर्माना के साथ ही जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर नगर निगम ने नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें लाइसेंस बनवाने के लिए 30 जून तक का मौका दिया गया है।

नोएडा : ठन्डे बस्ते में पड़ी वेंडिंग जोन पोलिसी

16 महीने बीतने के बाद भी नोएडामें वेंडिंगजोन का निर्धारण नहीं हो पाया है| हालाँकि 2 फ़रवरी 2019 को ही प्रशासन ने वेंडर जोन पोलिसी की सूचना जारी कर दी थी| 6600 वेंडरों ने ऑनलाइन आवेदन किया है जिनमें से सिर्फ 1142 को स्थायी लाइसेंस जारी होने हैं |

मुंबई: 70 हजार रेहड़ी वालों को लाइसेंस पाने का एक और मौक़ा मिलेगा| किसी कारण से जो अपात्र हैं या जो आवेदन नहीं कर पायें थे वे फिर एक बार आवेदन कर पाएंगे | यह फैसला टाउन वेंडिंग कमिटी की बैठक में मनपा अधिकारीयों को दिया गया|

७० हजार फेरीवाले होंगे पात्र?

जय सिंह / मुंबई

मुंबई की सडकों पर स्वरोजगार करनेवाले ७० हजार अपात्र फेरीवाले फिर अपने अधिकार के लिए प्रार्थना पत्र दे सकेंगे। यह हिदायत टाऊन वेंडिंग कमेटी की सभा में मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेसी ने मनपा अधिकारियों को दिया। मनपा आयुक्त का कहना था कि जो फेरीवाले अपात्र हैं, उनके आवेदन फिर मंगाए जाएं. इस आदेश के बाद मुंबई के ७० हजार फेरीवाले जो अपात्र हैं या किसी कारण से फॉर्म जमा नही कर पाए हैं, अब उनको भी लाइसेंस पाने का अधिकार मिलेगा। बता दें कि मनपा द्वारा किए गए सर्वे मे कुल १ लाख २८ हजार ४ ३५ फेरीवालो को फॉर्म बांटा गया था, जिनमे कुल ९९ हजार ६०० के करीब फेरीवालो का फॉर्म जमा हुआ था। इन जमा फॉर्म्स मे से मात्र १६ हजार फेरीवाले पात्र हैं। अपात्र फेरीवालो मे कई ऐसे हैं जो फॉर्म जमा ही नही कर पाए, कई ऐसे हैं जिनका डोमिसाइल न बन पाने के कारण फॉर्म जमा नही हो पाया है, कई ऐसे भी हैं जो मनपा कर्मचारियो की अनदेखी के कारण अपना सर्वे नही करा पाए। २१ जून को मनपा मुख्यालय मे मुंबई के फेरीवालो के टाऊन वेंडिंग कमेटी की सभा मे मनपा आयुक्त प्रवीण परदेसी सहित मुंबई के लाइसेंस विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे। इनके अलावा आजाद हॉकर्स युनियन के संस्थापक व फेरीवालो के नेता दयाशंकर सिंह, जनवादी हॉकर्स युनियन के महेंद्र सिंह, आयटक हॉकर्स युनियन के हैदर, महाराष्ट्र हॉकर्स युनियन के नवाज भाई व मनपा कर्मचारियो और फेरीवालो के नेता शशांक राव उपस्थित थे।

मुंबई में कुल 99434 वेंडरों का सर्वे हुआ है जिसमें से मात्र 16226 वेंडरों को ही पात्र माना गया है| टाउन वेंडिंग कमिटी ने अपात्र माने गए वेंडरों को उचित कागजात जमा करने के लिए और तीन महीने का समय दिया है| फेरी वालों से जुड़े समस्या के हल के लिए व्यवहारिक तरीकों को अपनाया जाना सराहनीय है|

पटियाला: 21 जून को पटियाला शहर नगर निगम के आंबेडकर हाल में नगर निगम कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा के नेतृत्व में टाउन वेंडिंग कमिटी की बैठक का आयोजन किया गया| बैठक में मुख्य रूप से शहर की सडकों पर लगाने वाली रेहड़ी पटरी को सुचारू रूप से लगाने की व्यवस्था पर चर्चा की गयी| शहर में अलग अलग जगहों पर वेंडिंग जोन बनाकर जगह जगह लग रही फलों की रेहड़ियों को सही तरीके से लगाने का विशेष प्रबंध किये जाने का फैसला लिया गया| वेंडिंग जोन की जगह पहचान करने के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है जो वेंडरों के रोजगार में कोई परेशानी ना आये इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित करेंगे| इस कमिटी में नगर निगम के अधिकारीयों के साथ पार्षद एवं स्ट्रीट वेंडर भी शामिल हैं| शहर में कुल 4025 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गयी है| शहर में पहली बार नगर निगम द्वारा वेंडिंग जोन में स्थान देने के लिए स्ट्रीट वेंडर लिसेंस भी जारी

किये जा रहे हैं| बैठक में वार्ड न० 54 के पार्षद विजय कुमार कूका, पार्षद संजीव कुमार स्ट्रीट वेंडर और टाउन वेंडिंग कमिटी के सदस्य के साथ सचिव नगर निगम भी सम्मिलित हुए|

रेहड़ी-फड़ी फैडरेशन के चुनाव सम्पन्न

टाईगर सिंह सर्वसम्मति से अध्यक्ष चयनित

लुधियाना: रेहड़ी-फड़ी फैडरेशन चुनाव उपरांत टाइगर सिंह अध्यक्ष निर्वाचित

स्ट्रीट वैंडर पॉलिसी शीघ्र लागू होने की संभावना

पंचकूला में का चुनाव

पंचकुला में 22 से 29 जुलाई तक होगी टाउन वेंडिंग चुनाव की प्रक्रिया| 8 सदस्यों के लिए होगा चुनाव|

टाउन वैंडर चुनाव की प्रक्रिया 22 से 29 जुलाई तक होगी

पंचकूला, 25 जून (मुकेश): हरियाणा स्ट्रीट वैंडर्स 6 के उपनियम (1) के तहत नगर निगम पंचकूला में टाउन वैंडर कमेटी के चुनाव करवाए जाएंगे। यह चुनाव कमेटी के 8 सदस्यों के लिये होंगे, जिनके लिए अलग-अलग वर्गों को आरक्षण के मुताबिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। नामांकन प्रक्रिया 22 जुलाई से 29 जुलाई तक होगी। नगर निगम पंचकूला के आयुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि इस 8 सदस्यीय समिति में एक पद अनुसूचित जाति महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ा वर्ग महिला और एक पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा। शेष चार पदों में एक पद सामान्य वर्ग महिला के लिए, तथा तीन पद सामान्य वर्ग श्रेणी में रखे हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि प्राप्त होने वाले नामांकन पत्रों की जांच 29 जुलाई को होगी।

6 जून 2019 को भारत सरकार गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा नेशनल शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत स्थानीय निकाय निदेशकों को रेहड़ी पटरी वालों के सर्वेक्षण करवाने का आदेश

Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
(UPA-II Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 6th June, 2019

To,
Principal Secretary
All States/UTs

Subject: Guidelines for development of model ULBs under SUSV-regarding.

Sir/Madam,

2. This issues with the approval of Mission Director & Joint Secretary (NULM).

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Surender Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:
Mission Directors (NULM), All States/UTs

Scanned by CamScanner

Guidelines to Develop Model ULB

बीकानेर: निगम सभागार में हुई टाउन वेंडिंग कमिटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा पहचान किये गए 2500 स्ट्रीट वेंडरों को प्रमाण पत्र दिए जाएँगे| बैठक में 21 स्ट्रीट वेंडिंग जोन तथा नो वेंडिंग जोन का प्लान बनाया गया|

NASVI
www.nasvinet.org